# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी )
# दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

**प्रेस विज्ञप्ति**

**26 मार्च 2011**

## 14 मार्च को दक्षिण बस्तर के चिंतलनार इलाके में मचाए गए सरकारी आतंक की निंदा करो!
## सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी आदिवासियों का नरसंहार, महिलाओं के साथ बलात्कार, गांव-दहन, पत्रकारों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले आदि काली करतूतों के खिलाफ
## 16-17 अप्रैल को दण्डकारण्य बंद सफल बनाओ!
## इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार दंतेवाड़ा एसएसपी कल्लूरी, आईजी लांगकुमेर समेत सभी दोषी पुलिस अधिकारियों और कोया कमाण्डों को गिरफ्तार करो!

14 मार्च 2011 के दिन आतंकी पुलिस, अर्धसैनिक व कोया कमाण्डो के करीब 300 बलों ने दक्षिण बस्तर के चिंतलनार क्षेत्र के कई गांवों पर हमला किया। जनता के बचाव में हमारे पीएलजीए बलों ने इन आतंकी बलों पर सुरपनगुड़ा गांव के पास हमला किया जिसमें तीन कोया कमाण्डो मारे गए जबकि 9 अन्य घायल हो गए। पीएलजीए के प्रतिरोध के सामने ये भाड़े के बल टिक नहीं सके और वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने ताड़मेटला, तिम्मापुरम और मोरपल्ली गांवों में जो कुछ किया उससे मानवता फिर एक बार शर्मसार हो गई। दूर-दराज के इस क्षेत्र से मिल रही खबरों के अनुसार पुलिस व कोया कमाण्डो बलों ने कम से कम छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, कम से कम तीन महिलाओं के साथ बलात्कार किया। कुछ महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी। इसके अलावा 300 से ज्यादा मकानों में आग लगा दी। यह विरल मौका था कि सरकारी आतंक से जुड़ी किसी वारदात का इस तरह पर्दाफाश हुआ हो और विधानसभा तक में चर्चा हुई हो।

23 मार्च तक इस अमानवीय हत्याकाण्ड व अग्निकाण्ड के बारे में जब मीडिया में खबरें आने लगीं तब प्रशासन का अमला जाग उठा ताकि अपनी साख बचाई जा सके। एक जांच कमेटी का गठन कर राहत सामग्री लेकर कलेक्टर और संभाग आयुक्त की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारी, यूनिसेफ के वाहन समेत कई वाहनों के काफिले के साथ पीड़ित गांवों के लिए रवाना हुए तो कई जगहों पर उन्हें रोका गया। यहां तक कि वाहनों के ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की गई। अगले दिन सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के साथ-साथ कई जनवादी लोगों का एक दल जब राहत सामग्री लेकर जा रहा था, उन पर अण्डे फेंके गए और राहत सामग्री लूट ली गई। इस दल के साथ जा रहे कई पत्रकारों के साथ भी सलवा जुडूम के गुण्डों और एसपीओ ने हाथापाई की और पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए। ऊपर से देखने वालों को यह सब स्थानीय स्तर पर कुछ सलवा जुडुमियों या एसपीओं के द्वारा किए जाने वाला कारनामा लगता हो, लेकिन सच यह है कि इसका नियंत्रण पुरा रायपुर से हो रहा था जिसकी कमान मुख्यमंत्री रमनसिंह, डीजीपी विश्वरंजन के साथ-साथ उनके वफादार सेवक बस्तर आईजी लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एसएसपी कल्लूरी के हाथों में थी। यह कोई नई घटना भी नहीं है। बस्तर क्षेत्र में सरकारी दमन से जुड़े मामलों की विवेचना करने आए हर दल पर ऐसे हमले सालों से होते रहे हैं। यहां पर सरकारी आतंक के विरोध में खबरें लिखने वाले पत्रकारों के साथ मारने की धमकियों से लेकर मारपीट की घटनाएं आम हैं। पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, समाजशास्त्री जैसे लोगों के साथ यहां यह सब होता है तो यहां के दूर-दराज के गांवों में स्थित आदिवासियों की हालत क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां पर लोगों के जीने के अधिकार समेत संविधान द्वारा प्राप्त तमाम तथाकथित बुनियादी अधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन आम बात है।

आदिवासियों का नरसंहार, महिलाओं के साथ बलात्कार और गांव-दहन का यह पहला मामला भी नहीं है। पहले सलवा जुडूम और बाद में 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से 2005 से लगातार जारी फासीवादी दमनचक्र में सरकारी सशस्त्र

बलों ने सैकड़ों गांवों में हजारों घरों को जला दिया। एक-एक गांव को एक बार नहीं, कई बार जला दिया। एक ही गांव को किश्तों में जला दिया। किसी-किसी गांव के सभी घरों को एक साथ आग के हवाले कर दिया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की भयावहता को समझने के लिए बस एक आंकड़ा काफी है - 2008 में बीजापुर के पास सिर्फ 10 गांवों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 74 महिलाओं के साथ सरकारी बलों ने बलात्कार किया। इनमें कइयों के साथ सामूहिक बलात्कार, कई दिनों तक बलात्कार हुआ। लोगों की अंधाधुंध हत्याएं, बर्बर व पाशविक तरीके से की गई हत्याएं एक साधारण सी बात हो गई। 14 मार्च की घटना इसकी धारावाहिकता भर थी।

कुछ सप्ताह पहले नारायणपुर जिले में हमारी पीएलजीए द्वारा गिरफ्तार पांच पुलिस वालों की रिहाई के मौके पर जब स्वामी अग्निवेश आए थे, तो रमनसिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया था और लगे हाथों माओवादियों के साथ वार्ता की पेशकश तक कर डाली थी। आज उसी अग्निवेश पर अण्डे फेंकवाए जो पुलिसिया दमन का शिकार हुए गांवों का दौरा करने की कोशिश कर रहे थे। इससे रमनसिंह का फासीवादी चेहरा साफ तौर पर उजागर हो जाता है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना घोर विरोधी है।

**प्यारे लोगो व लोकतंत्र के प्रेमियो!**

आज बस्तर क्षेत्र में सरकारी आतंक का नंगा नाच चल रहा है। दरअसल सरकारी दमन की रोजमर्रा की घटनाओं में सिर्फ कुछ ही रोशनी में आ पाती हैं, अधिकांश को दबा दिया जाता है। अब जबकि आप हमारा यह वक्तव्य पढ़ रहे हों, कहीं न कहीं पुलिस का डंडा किसी मासूम आदिवासी के बदन को तोड़ रहा होगा... किसी आदिवासी बाला को उनके हाथों नोंच डाला जा रहा होगा... किसी आदिवासी युवक की झूठी मुठभेड़ में मारने की कोशिशें हो रही होगी... किसी गांव पर आतंक का तांडव मचाया जा रहा होगा। दमन यहां के लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां पर माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया कर इस पूरे क्षेत्र को बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूटखसोट के चारागाह में तब्दील किया जा सके। टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, निको जैसी लुटेरी कम्पनियां ताक में बैठी हुई हैं जिनके साथ रमन सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के एमओयू कर रखे हैं। लूट और दलाली के इस विनाशकारी खेल में रमन सरकार लाखों आदिवासियों को विस्थापित कर उनके अस्तित्व को खत्म करने पर आमादा है। यह हमला केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश पर सभी राज्य सरकारों से तालमेल के साथ चल रहा है जिसका हिस्सा ही है चिंतलनार क्षेत्र की यह ताजा घटना। हम खासतौर पर आदिवासी समाज के प्रमुखों से जो राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी से क्यों न जुड़े हुए हों, अपील करते हैं कि वे सरकारी आतंक के खिलाफ तथा आदिवासी समाज पर हो रहे इस भयावह हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हम पत्रकारों और मीडिया के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वे इस हमले का विरोध करें और जनता के पक्ष में मजबूती से खड़े हों। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग से आंदोलन करें।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी समूची जनता का यह आह्वान करती है कि चिंतलनार क्षेत्र में मचाए सरकारी आतंक के विरोध में, इस तरह की तमाम घटनाओं के विरोध में आगामी 16 व 17 अप्रैल को 48-घण्टों तक 'दण्डकारण्य बंद' को सफल बनाया जाए। इस मौके पर आर्थिक नाकेबंदी भी रहेगी जिस दौरान दण्डकारण्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि पर रोक रहेगी। हालांकि हम छात्रों की परीक्षाओं तथा स्वास्थ्य आदि आवश्यक सुविधाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

Gudsa Usendi

**(गुड्सा उसेण्डी)**

**प्रवक्ता**

**दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी**

**भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**